

स्टूडेंट्स की बेहतर होगी स्किल

कोई चाहे तो एक साथ बीकॉम और साइंस में भी डिग्री ले सकता है। अगर कोई एक ही यूनिवर्सिटी से दोनों विषयों की ऑफलाइन डिग्री की पढ़ाई कर रहा है तो यह देखना होगा कि उनके क्लास एक ही समय में ना हों।

नीतू शाह।।

जिन कॉलेजों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) और भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों की मान्यता है, उनसे अकादमिक सत्र 2022-23 से डिप्लोमा, अंडर ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट लेवल पर स्टूडेंट्स एक साथ दो विषयों में डिग्री ले सकते हैं। यूजीसी का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स की रिक्ल क्षेत्र होगी। दोनों डिग्रियां एक साथ क्लास में पढ़ाई, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन या दोनों ऑनलाइन तरीके से ली जा सकती हैं।

यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसे अपनाने या नहीं अपनाने की आजादी यूनिवर्सिटी को दी इस मामले में दो संस्थानों से गई है। किन-किन विषयों में एक साथ दो भी पढ़ाई करने की इजाजत देती है। यह लेकिन यह तभी मुफीद होगा, जब दोनों

अलग—अलग संस्थानों पर निर्भर करेगा। इससे किसी स्टूडेंट को एक साथ साइंस से डिग्री लेने की आजादी मिलेगी। कोई चाहे तो एक साथ बीकॉम और साइंस में भी डिग्री ले सकता है। अगर कोई एक ही यूनिवर्सिटी से दोनों विषयों की ऑफलाइन डिग्री की पढ़ाई कर रहा है तो यह देखना होगा कि उनके क्लास एक ही समय में ना हों। ऐसे में



शिफ्ट में कर सकता है।

संस्थान आसपास हों। एक साथ दो डिग्री के लिए योग्यता की शर्तें और यूनिवर्सिटी के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूजीसी का कहना है कि यह पहल नई शिक्षा नीति के तहत की गई है। इसका मकसद अलग—अलग डिसिप्लिन में पढ़ाई का मौका देकर उनके हुनर को निखारना है। इससे ऐसे स्टूडेंट्स की रोजगार पाने की संभावना बेहतर होगी। लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी हैं। पहला तो यही है कि एक ही विषय से डिग्री लेने में एक और तेज करनी होगी। यानी इस मामले में एक व्यापक सोच की जरूरत है, जिससे उच्च शिक्षा में देश का दर्जा बेहतर हो।

डिग्री का प्रेशर सह पाएगा? दूसरा सवाल शिक्षा के स्तर से जुड़ा हुआ है। कई कंपनियां, सर्वे में यह बात सामने आई है कि भारत में एक हव तक शिक्षित छात्रों में भी रोजगार पाने की योग्यता नहीं होती। इसलिए एक साथ दो डिग्री की पहल के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की भी पहल करनी होगी। एक और समस्या उच्च शिक्षा में घटती दिलचस्पी की भी है। यूजीसी और अन्य सरकारी एजेंसियों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ, देश की अधिक से अधिक यूनिवर्सिटीज अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक में अपनी जगह बना पाएं, इसके लिए कांशिशें और तेज करनी होंगी। यानी इस मामले में एक व्यापक सोच की जरूरत है, जिससे उच्च शिक्षा में देश का दर्जा बेहतर हो।

संपादकीय

आम लोगों से संवाद

विधानसभा चुनावों के दौरान एटा के जलेसर में एक निष्ठावान कांग्रेसी मिल गए। नाम था रामसेवक। जब उनसे पूछा कि कांग्रेस क्यों नहीं मजबूती से लड़ पा रही है, तो रामसेवक बोले, 'पार्टी ऐसे लोगों के भरोसे हो गई है जिन्हे जमीनी जानकारी नहीं।' कांग्रेस को आम लोगों के बीच जाकर संवाद स्थापित करना होगा। संघर्ष, संवाद और विचार से लड़ाई जीती जा सकती है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज ही किसी पार्टी को बलशाली बना सकती है। अखिर हम प्रबंधन में सफलता क्यों ढूँढ़ना चाहते हैं? क्यों सेवा, संवाद और विचार में सफलता को नहीं खोज रहे हैं? याद आ रहा है कि नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव सभी विधानमंडल दल की लंबी बैठकें करते थे और हर विधायक की बात बहुत ध्यान से सुनते थे। विधायक भी खुलकर अपनी बात कहते, जिससे पार्टी मजबूत हो। अब अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भरोसा कम हो गया है। यह संयोग भी बड़ा अर्थपूर्ण है कि जिस समय कांग्रेस पीके में सफलता के ब्रह्मास्त्र ढूँढ़ रही थी उसी दौरान पीके की कंपनी ने कांग्रेस की धुर विरोधी तेलंगाना की टीआरएस से चुनावी प्रबंधन का समझौता कर लिया। कांग्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी को अपने युवा और अनुभवी नेताओं पर भरोसा करना चाहिए। उन्हीं से फीडबैक लेना चाहिए। उन्हीं से विचार लेना चाहिए और फिर जनता के बीच जाना चाहिए। कोई सेना भाड़े के सैनिकों से युद्ध नहीं जीत सकती। उसे अपने समर्पित सैनिकों पर भरोसा करना ही होगा। जो लोग प्रबंधन में सफलता ढूँढ़ना चाहते हैं वे भ्रम के शिकार हैं। शायद उन्हें जमीनी जानकारी नहीं है।

चुनावी प्रबंधन के गुरु माने जाने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को टुकरा दिया कि वह पार्टी में शामिल हो जाएं। सवाल है, क्या देश की राजनीति में पुरुषार्थ के दिन लद गए और उसका स्थान प्रबंधन ले रहा है? क्या भारत की राजनीति नए मार्ग की ओर बढ़ रही है? अब राजनीति के मुद्दे और उसकी दिशा राजनीति के तपे—तपाए नेता नहीं बल्कि चुनाव जिताने का दावा करने वाले प्रबंधक तथ करेंगे? इस सिलसिले की मजबूत शुरुआत 2014 से हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी। नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए और प्रधानमंत्री बन गए। इससे राजनीतिक दलों को लगा कि यह जीत मोदी की कम, पीके की ज्यादा है। इसके बाद दलों के नेता और कार्यकर्ता पीछे की सीट पर बैठा दिए गए और प्रबंधक ड्राइविंग सीट पर जा बैठे।

बात 2017 की है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी पीके को दे दी गई थी। पीके की ही सलाह पर कांग्रेस ने खाट यात्रा शुरू की। गांव में खाट में बैठे हजारों ग्रामीणों के बीच राहुल गांधी उनसे चर्चा करते थे। इस खाट

यात्रा से कांग्रेस को क्या मिला, कुछ पता नहीं चला। लेकिन गांव वाले उन खाटों को अपने घर जरूर उठा ले गए। जब कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी होती नहीं दिखी तो समाजवादी पार्टी से समझौता किया गया। लेकिन पीके की कोई राजनीति काम नहीं आई और चुनाव में कांग्रेस की खाट खड़ी हो गई। वैसे अकेले कांग्रेस की ही बात क्यों की जाए। अब तो चुनावी प्रबंधन के लिए सभी राजनीतिक दल कंपनियों के भरोसे हो गए हैं। इतना जरूर है कि कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। शायद कांग्रेस के नीति नियंताओं को लगा कि वे पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते, पीके के पास कोई जादू की छड़ी है जिससे वह पार्टी को मजबूत कर देंगे। सवाल बड़ा है। क्या किसी पार्टी का जनाधार मुद्दों को तलाश कर बढ़ाया जा सकता है? असल में एक आम धारणा रही है कि जो नेता जमीन पर हैं, उनसे बेहतर मुद्दे कोई नहीं जानता और उनसे ज्यादा लोगों

की कोई सेवा भी नहीं कर सकता। इस धारणा के उलट, विभिन्न दलों के बड़े-बड़े नेताओं के चुनावी प्रबंधकों के इशारे पर नाचने की शुरुआत हो चुकी है। क्या अब नेताओं को सेवा के रास्ते बताए जाएंगे? यह राजनीति के लिए बहुत ही दुखद दिन हो सकता है जब हमारे जमीनी नेताओं को असफल मान लिया जाए और चुनावी प्रबंधक यह बताने लगें कि किस रास्ते पर चलकर चुनाव जीता जा सकता है। जो जन प्रतिनिधि जमीन पर है उससे बड़ा चुनावी प्रबंधक कोई दूसरा नहीं हो सकता। कालजयी सावित हुए नारों को इन नए चुनावी प्रबंधकों ने नहीं बल्कि जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गढ़ा। 'मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ' के नारे ने चुनाव को पलट दिया था। 'अच्छे दिन आने वाले हैं, यह नारा सुषमा चरवाज के दिमाग की उपज था न कि किसी चुनावी प्रबंधक के दिमाग की। देश की जनता भूखी है, यह आजादी झूठी है का नारा वामपंथियों ने गढ़ा था। समाजवादियों के नारे भी जन-जन तक पहुँचे।

वास्तव में राजनीति की जो नई धारा आई है, उसमें कम मेहनत में बहुत कुछ पाने की तमन्ना है और इसी बजह से यह उस चुनावी प्रबंधन पर पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहती है, जो कॉरपोरेट कल्चर से निकली है।

अपना ब्लॉग मतदाता के मन में अपने लिए मजबूत जगह

मोहन। राजनीति के जो मंजे खिलाड़ी हैं, वे जानते हैं कि राजनीतिक सफलता के कौन से गुर हैं। जो समाजसेवा करते हुए तप चुका है, वहीं चुनावी रणनीति का पुरोधा हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना और कांग्रेस के महराजपुर से विधायक हैं, जिनकी जाति के एक हजार वोट भी उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं हैं। लेकिन ये दोनों लगातार नौ बार से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अब चुनावी प्रबंधन के नाम पर निकले लोगों को दलों पर ही स्थापित करने का प्रयास दलों द्वारा हो तो फिर इसका मतलब यही निकला कि सेवा का कोई मूल्य नहीं, प्रबंधन ही सब कुछ है। इसी तरह कांग्रेस के नेता प्रमोट तिवारी दस बार और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां लगातार दस बार चुनाव जीत चुके हैं। इन सबने प्रबंधन से नहीं बल्कि सेवा और संवाद से मतदाता के मन में अपने लिए मजबूत जगह बनाई। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सेवा का रास्ता कोई दूसरा नहीं बता सकता।


<tbl